

समक्ष प्रेम चंद जैन, ए.सी.जे & जे.एम टंडन, माननीय

न्यायमूर्ति।

बाबू राम और अन्य – याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य, – प्रतिवादियों

1976 की सी.ट्रि.याचिका नंबर 7208

29 मई, 1984

हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम (1973 का 20)-धारा 38-हरियाणा सामान्य बिक्री कर नियम; 1975-नियम 53-भारत का संविधान 1950 अनुच्छेद 246(3) और सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 54 पारिश्रमिक के भुगतान पर अपने ग्राहकों की ओर से माल की बुकिंग/डिलीवरी लेने के लिए सेवाएं प्रदान करने वाले समाशोधन/अग्रेषण एजेंट-धारा 38 की आवश्यकता है ऐसे एजेंटों को लाइसेंस लेने और उनके द्वारा संभाले गए माल की निर्धारित जानकारी प्रस्तुत करने के लिए प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान है - धारा 38 और नियम 53 - चाहे वह राज्य विधानमंडल की शक्तियों से परे हो।

अभिनिर्णित, विधानमंडल मुख्य प्रावधान के प्रासंगिक और सहायक मामलों के संबंध में कानून बनाने में सक्षम है, बशर्ते कि वे अनुसूची के प्राथमिक प्रमुख द्वारा प्रदत्त शक्तियों से संबंधित हों। सातवीं अनुसूची की सूची II, प्रविष्टि 54 के तहत कानून बनाने की आकस्मिक और सहायक शक्ति को माल की बिक्री या खरीद के लिए पूरी तरह से अजनबी को कवर करने के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है। हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 की धारा 38 में प्रावधान है कि एक समाशोधन या अग्रेषण एजेंट या दलाई तब तक अपना व्यवसाय नहीं करेगा जब तक कि वह मूल्यांकन प्राधिकारी से लाइसेंस प्राप्त नहीं कर लेता है और इसके अलावा उसके लिए मूल्यांकन प्राधिकारी को विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है। और माल के लेन-देन के संबंध में जानकारी ऐसे प्रारूप और तरीके से दी जाएगी जो निर्धारित की जा सकती है। उल्लंघन की स्थिति में, वह उस सामान के मूल्य के 20 प्रतिशत के बराबर राशि का जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी है जिसके संबंध में कोई विशेष या जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। एक समाशोधन या अग्रेषण एजेंट या दलाई है। माल की बिक्री या खरीद के लेन-देन के लिए कोई अजनबी, वह बिक्री-कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है और न ही वह इसकी चोरी के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि वह डीलर नहीं है। इसके अलावा, बिक्री-कर की चोरी का अनुमान लगाने का शायद ही कोई औचित्य है। उन लेनदेन में जिनके संबंध में एक एजेंट या दलाई को अधिनियम की धारा 38 के तहत मूल्यांकन प्राधिकारी को विवरण और

जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। इसी तरह, लेन-देन में बिक्री-कर की चोरी मानना गलत होगा, जिसका विवरण और जानकारी एक एजेंट या दलाई मूल्यांकन प्राधिकारी को प्रस्तुत करने में विफल रहा है। इसके अलावा, बिक्री-कर की चोरी के संबंध में जिम्मेदारी, यदि कोई हो, डीलर की है और इसे उचित रूप से एजेंट या दलाई पर नहीं थोपा जा सकता है। बिक्री कर का भुगतान करने के लिए एजेंट या दलाई का कोई दायित्व नहीं है या उसके भुगतान से बचने के लिए उसकी ओर से कोई प्रयास या उसके खिलाफ संदेह है, यह नहीं माना जा सकता है कि अधिनियम की धारा 38 में निहित प्रावधान राज्य विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत हैं। संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II, प्रविष्टि 54 के तहत बिक्री कर लगाने की शक्ति के लिए सहायक और आकस्मिक। इसलिए, अधिनियम की धारा 38 राज्य विधानमंडल के अधिकार के बाहर है क्योंकि यह न तो सीधे तौर पर सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 54 सूची II में शामिल है और न ही यह उसकी सहायक या आकस्मिक है। नियम 53 अधिनियम की धारा 38 का परिणामी होने के कारण असंवैधानिक भी है।

(पैरा 20 और 23)

इस मामले में शामिल कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्णय के लिए माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रेम चंद जैन द्वारा 19 अक्टूबर, 1982 को मामले को बड़ी पीठ के पास भेजा गया। माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, श्री प्रेम चंद जैन और माननीय श्री न्यायमूर्ति जे.एम. टंडन की बड़ी पीठ ने अंततः 29 मई, 1984 को मामले का फैसला किया।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका, प्रार्थना करते हुए कि यह माननीय न्यायालय जारी करने की कृपा करे: -

(ए) नियम;

(बी) परमादेश की प्रकृति में धारा 38 और नियम 53 के प्रावधानों को भारत के संविधान के अधिकारेतर घोषित करने वाला एक रिट;

(सी) प्रतिवादियों को याचिकाकर्ताओं को रिटर्न दाखिल करने के लिए बाध्य करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा की प्रकृति की एक रिट जारी की जाएगी;

(डी) याचिकाकर्ताओं द्वारा मासिक रिटर्न दाखिल करने सहित प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के समक्ष आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने वाला विज्ञापन-अंतरिम आदेश, इस रिट याचिका के लंबित निपटान के लिए दिया जाए;

(ई) इस याचिका की लागत की अनुमति दी जाए।

इसके अलावा, प्रार्थना है कि कोई भी रिट, आदेश या निर्देश, जिसे यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित समझे, जारी किया जाए।

याचिकाकर्ता के वकील आर. पी. साहनी।

प्रतिवादी की ओर से गोपी चंद, वकील।

निर्णय

जे.एम.टंडन, माननीय न्यायमूर्ति।

- (1) याचिकाकर्ता क्लियरिंग/अग्रेषण एजेंट हैं और पारिश्रमिक के भुगतान पर अपने ग्राहकों की ओर से रेलवे स्टेशनों पर माल की बुकिंग और/या डिलीवरी लेने के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उनके व्यापार की सामान्य प्रथा यह है कि वे अपने ग्राहकों के निर्देश पर रेलवे द्वारा परिवहन किए जाने वाले माल की बुकिंग की व्यवस्था करते हैं और अपने ग्राहकों के नाम पर आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करते हैं। वे अपने ग्राहकों की ओर से रेलवे रसीद के आधार पर माल की डिलीवरी भी लेते हैं और सामान और दस्तावेज अपने ग्राहकों को सौंप देते हैं।

हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973, (इसके बाद अधिनियम) 5 मई, 1973 को हरियाणा राज्य में लागू हुआ अधिनियम की धारा 38 में लिखा है: -

“38. समाशोधन और अग्रेषण एजेंटों, आदि द्वारा जानकारी प्रस्तुत करना-

- (1) समाशोधन या अग्रेषण एजेंट, दलाल या राज्य के भीतर माल परिवहन करने वाला कोई अन्य व्यक्ति, जो अपने व्यवसाय के दौरान, किसी डीलर के लिए या उसकी ओर से माल के स्वामित्व के दस्तावेजों को संभालता है, मूल्यांकन प्राधिकारी को विवरण प्रस्तुत करेगा। और माल के लेन-देन के संबंध में जानकारी ऐसे प्रारूप और तरीके से दी जाएगी, जैसा निर्धारित किया जा सकता है।
- (2) कोई भी समाशोधन या अग्रेषण एजेंट, दलाल या राज्य के भीतर माल परिवहन करने वाला कोई अन्य व्यक्ति तब तक अपना व्यवसाय नहीं करेगा जब तक कि वह मूल्यांकन प्राधिकारी से पचास रुपये से अधिक शुल्क के भुगतान पर, फॉर्म और तरीके से और ऐसी शर्तों के अधीन लाइसेंस प्राप्त नहीं कर लेता है। , जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
- (3) यदि कोई समाशोधन या अग्रेषण एजेंट या दलाल या राज्य के भीतर माल परिवहन करने वाला

व्यक्ति उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो आयुक्त या उप-धारा के तहत उसकी सहायता के लिए नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति (1) धारा 3 के अनुसार, संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, उसे जुर्माने के रूप में माल के मूल्य के बीस प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जा सकता है, जिसके संबंध में कोई विवरण और जानकारी नहीं दी गई है। उपधारा (1) के तहत प्रस्तुत किया गया है।

स्पष्टीकरण-इस अनुभाग के प्रयोजन के लिए-

- (i) 'दलाल' में वह व्यक्ति शामिल होगा जो रेलवे स्टेशन, बुकिंग एजेंसी, माल परिवहन कंपनी कार्यालय, या माल की लोडिंग या अनलोडिंग के किसी भी स्थान पर माल की खेप की बुकिंग, या डिलीवरी लेने के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करता है। किसी भी डीलर के लिए या उसकी ओर से शुल्क, इनाम, कमीशन, पारिश्रमिक¹या अन्यथा के लिए सौदेबाजी और अनुबंध करता है, करता है/और निष्कर्ष निकालता है;
- (ii) माल परिवहन करने वाले व्यक्ति में, मालिक के अलावा, प्रबंधक, एजेंट, ड्राइवर, मालिक के कर्मचारी

या माल की लोडिंग या अनलोडिंग की जगह (या रेलवे आउट एजेंसी, शहर बुकिंग कार्यालय) के प्रभारी व्यक्ति शामिल होंगे। या सिटी बुकिंग एजेंसी, जब रेलवे के साथ एक अनुबंध के तहत एक निजी व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है, लेकिन रेल हेड या पोस्ट ऑफिस को छोड़कर) या ऐसा माल ले जाने वाला माल वाहक या ऐसा व्यक्ति जो अन्य स्थानों पर भेजने के लिए ऐसे माल की खेप स्वीकार करता है या ऐसे माल की किसी भी खेप की डिलीवरी कंसाइनी को देता है।

अधिनियम की धारा **64** के तहत बनाए गए हरियाणा सामान्य बिक्री कर नियम, **1975** (इसके बाद नियम) **5** नवंबर, **1975** को लागू हुए, नियमों के नियम **53** में लिखा है: -

“53. समाशोधन और अग्रेषण एजेंटों द्वारा जानकारी प्रस्तुत करना।

प्रत्येक समाशोधन या अग्रेषण एजेंट या दलाल, धारा **38** की उपधारा (1) के तहत अपेक्षित, लाइसेंस देने वाले निर्धारण प्राधिकारी को फॉर्म एस.टी. में रिटर्न प्रस्तुत करेगा। **43** प्रत्येक माह के समापन के दस दिनों की अवधि के भीतर माह के दौरान उसके द्वारा संभाली गई खेपों के संबंध में और फॉर्म एस.टी. में सही और सही रिकॉर्ड रखेगा और बनाए रखेगा। **44** उसके द्वारा संभाले गए माल की खेप के संबंध में।

संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 11 की प्रविष्टि 54 में लिखा है:-

समाचार पत्रों के अलावा अन्य वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर कर, सूची 1 की प्रविष्टि 92-ए के प्रावधानों के अधीन।"

- (2) यह अधिनियम राज्य विधानमंडल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 246(3) के साथ पढ़ी गई प्रविष्टि 54 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए बनाया गया है। याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान रिट में अधिनियम की धारा 38 और नियमों के नियम 53 की वैधता को चुनौती दी है।
- (3) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि अधिनियम की धारा 38 और नियमों के नियम 53 राज्य विधानमंडल की क्षमता से बाहर हैं और सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 54 के दायरे से बाहर हैं क्योंकि वे व्यक्तियों (जैसे याचिकाकर्ताओं) से संबंधित हैं।) जो किसी भी तरह से माल की बिक्री या खरीद से जुड़े नहीं हैं। तर्क यह है कि याचिकाकर्ता पारिश्रमिक के लिए अपने ग्राहकों की ओर से रेलवे स्टेशन तक माल लाने-ले जाने का काम करते हैं। वे अधिनियम के तहत बिक्री-कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। राज्य विधानमंडल दूसरों द्वारा बिक्री कर की चोरी का पता लगाने के उद्देश्य से

याचिकाकर्ताओं की तरह सामान खरीदने या खरीदने के लिए अजनबियों की सेवाओं का उपयोग करने के लिए संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 54, सूची II के तहत कानून नहीं बना सकता है।

- (4) राज्य के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता समाशोधन/अग्रेषण एजेंट होने के नाते माल की बिक्री या खरीद के लिए अजनबी नहीं हैं, क्योंकि वे ऐसी बिक्री या खरीद के दौरान अपने ग्राहकों की ओर से रेलवे स्टेशन तक माल ले जाते हैं। . तर्क आगे बढ़ता है कि यह मानते हुए कि याचिकाकर्ता समाशोधन/अग्रेषण एजेंट के रूप में किसी भी तरह से माल की बिक्री या खरीद से जुड़े नहीं हैं, राज्य विधानमंडल अधिनियम की धारा 38 को लागू करने में सक्षम है, जो मुख्य प्रावधान के लिए सहायक और आकस्मिक है। वह अधिनियम जो स्वीकार्य रूप से सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 54, सूची II द्वारा कवर किया गया है।
- (5) विचार करने वाला पहला बिंदु यह है कि क्या याचिकाकर्ता किसी भी तरह से प्रविष्टि 54, सातवीं अनुसूची की सूची II के संदर्भ में माल की बिक्री या खरीद से जुड़े हुए हैं या नहीं।

- (6) उत्पाद शुल्क एवं कराधान अधिकारी ने राज्य की ओर से दायर लिखित बयान में निम्नलिखित बातें कही हैं:

“आम बोलचाल में ‘दलाई’ एक सुस्थापित व्यवसाय है। ये दलाल (याचिकाकर्ता) अपने ग्राहकों, यानी विभिन्न प्रकार के डीलरों की ओर से रेलवे स्टेशन पर काम करते हैं। डीलर इन दलालों के माध्यम से अपना माल रेलवे स्टेशन पर बुकिंग के लिए भेजते हैं और माल को उनके गंतव्य तक भेजने के लिए रेलवे स्टेशन पर सभी औपचारिकताएं-इन्हीं दलालों द्वारा पूरी की जाती हैं। इसी प्रकार, जब डीलरों का कुछ सामान रेलवे स्टेशनों पर प्राप्त होता है, तो डीलरों द्वारा डिलीवरी इन दलालों के माध्यम से ली जाती है। यह देखा गया है कि आम तौर पर विभिन्न डीलरों द्वारा फर्जी लेनदेन किया जाता है। फर्मों द्वारा माल को फर्जी नामों से बुक किया जाता है और इन्हें फर्जी नाम से कंसाइनी फर्म को संबोधित किया जाता है और इस तरह कर के रूप में राज्य का राजस्व खतरे में पड़ता है। इन फर्जी लेनदेन के कारण विभाग वास्तविक व्यक्ति तक नहीं पहुंच सका। कर चोरी को रोकने और राज्य के राजस्व की सुरक्षा के लिए कराधान कानून के दायरे में लाने के लिए, धारा 38 को हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) में शामिल किया गया था। अधिनियम की धारा 38 के प्रावधानों के मद्देनजर

दलालों पर लाइसेंस प्राप्त करने और फॉर्म एसटी में जानकारी बनाए रखने का शुल्क लगाया गया है। 44 एवं एस.टी. प्रपत्र में मासिक रूप से विभाग को उपलब्ध करायें। 43 क्योंकि दलाल अच्छी तरह जानते हैं कि असली डीलर कौन हैं।

अधिनियम की धारा 38 को लागू करने के पीछे का उद्देश्य याचिकाकर्ताओं को दंडित करना नहीं है, बल्कि फर्जी लेनदेन और फर्जी नामों के माध्यम से की जाने वाली कर चोरी को रोकना है।

यहां यह उल्लेख करना और भी प्रासंगिक है कि डीलरों की ओर से रेलवे के साथ माल बुक कराने और दलालों के माध्यम से डीलरों द्वारा रेलवे से माल की डिलीवरी प्राप्त करने का व्यापार बिक्री के व्यवसाय के लिए सहायक और आकस्मिक है। और माल की खरीद। राज्य विधानमंडल को माल की बिक्री या खरीद पर कराधान के लिए कानून बनाने के लिए भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची II की प्रविष्टि 54 के तहत अधिकार प्राप्त है।

याचिकाकर्ताओं की आजीविका किसी भी तरह से नहीं छीनी गई है। बल्कि याचिकाकर्ताओं को लाइसेंस प्राप्त करने और मासिक रिटर्न प्रस्तुत करने से राज्य को फर्जी लेनदेन का पता लगाने में मदद मिलेगी और

कर चोरी को रोका जा सकेगा। कर चोरी का पता लगाना समाज के कल्याण के लिए फायदेमंद होगा। इसलिए इस तरह वे राज्य को ऐसे लेनदेन पर कर की वसूली में प्रोत्साहन देने में मदद करेंगे जो कुछ डीलरों द्वारा फर्जी नामों से किए जाते हैं।

- (7) याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि वे किसी भी तरह से माल की बिक्री या खरीद से जुड़े नहीं हैं। उनके द्वारा किये गये कार्य की प्रकृति उनकी दलील का समर्थन करती है। याचिकाकर्ता निश्चित रूप से न तो डीलर हैं और न ही अधिनियम के तहत बिक्री कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। हालाँकि, राज्य की ओर से दायर लिखित बयान में यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई आधार नहीं रखा गया है कि याचिकाकर्ता अपने ग्राहकों की ओर से समाशोधन/अग्रेषण एजेंटों के रूप में उनके द्वारा संभाले गए सामानों की बिक्री या खरीद के लिए अजनबी नहीं हैं। याचिकाकर्ताओं से संबंधित अधिनियम की धारा 38 पूरी तरह से दूसरों (डीलरों) द्वारा किए गए फर्जी लेनदेन का पता लगाने के लिए उनकी सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाई गई है।
- (8) अगला मुद्दा जो विचार के लिए उठता है वह यह है कि क्या राज्य विधानमंडल सीधे तौर पर याचिकाकर्ताओं को शामिल करने के लिए कानून बनाने

में सक्षम है, जो समाशोधन/अग्रेषण एजेंट और दलाल के रूप में माल की बिक्री या खरीद के लिए अजनबी हैं और बिक्री कर के भुगतान या चोरी के लिए भी जिम्मेदार नहीं हैं। *Epry 54, VII* अनुसूची की सूची // के तहत।

- (9) ओरिएंट पेपर मिल्स लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य में, (1), यह आयोजित किया गया था: -
संविधान की अनुसूची में कानून के विविध प्रमुख विधायी क्षमता की परिधि का सीमांकन करते हैं और इसमें वे सभी मामले शामिल होते हैं जो प्राथमिक प्रमुख के सहायक या सहायक होते हैं। इसलिए, उड़ीसा राज्य का विधानमंडल अनुसूची 7, सूची 2, मद 54 के तहत अनुचित या अवैध रूप से एकत्र कर की वापसी देने के सहायक या सहायक मामले के संबंध में शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम था। यदि अनुचित तरीके से एकत्र किए गए बिक्री कर का रिफंड देने के लिए कानून बनाने की क्षमता प्रदान की जाती है, तो यह घोषित करने की शक्ति को बाहर करने का कोई कारण नहीं है कि रिफंड का दावा केवल उस व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, जिससे डीलर ने वास्तव में बिक्री कर या अन्यथा के माध्यम से रकम की वसूली की है।”

(10) आर. अब्दुल क्वाडर एंड कंपनी बनाम सेल्स टैक्स ऑफिसर, सेकेंड सर्कल, हैदराबाद, (2) मामले में, यह माना गया कि यदि किसी डीलर ने किसी खरीदार से कुछ भी एकत्र किया है जो कर कानून द्वारा अधिकृत नहीं है, तो यह बीच का मामला है वह और क्रेता, और क्रेता डीलर से राशि वसूलने के हकदार हो सकते हैं। लेकिन जब तक तथाकथित धन कर के रूप में देय नहीं होता है, राज्य कानून द्वारा इसे केवल इसलिए वसूली योग्य नहीं बना सकता है, क्योंकि यह डीलर द्वारा गलत तरीके से एकत्र किया गया है। यह सीधे तौर पर नहीं किया जा सकता क्योंकि यह सूची II की प्रविष्टि 54 के अर्थ के तहत बिल्कुल भी कर नहीं है, न ही राज्य विधानमंडल आकस्मिक या सहायक शक्ति की आड़ में अप्रत्यक्ष रूप से वह कर सकता है जो वह सीधे नहीं कर सकता।

(11) आर. अब्दुल क्वाडर के मामले (सुप्रा) में उनके आधिपत्य ने ओरिएंट पेपर मिल के मामले (सुप्रा) पर ध्यान दिया और निम्नलिखित टिप्पणियां करके इसे अलग किया: -

“वह मामला रिफंड के प्रश्न 1 2 से संबंधित है और इसमें संदेह नहीं किया जा सकता है कि एकत्रित कर का रिफंड हमेशा कर लगाने और संग्रह से संबंधित आकस्मिक और सहायक शक्तियों द्वारा कवर किया गया मामला है। वर्तमान मामले में हम रिफंड के मामले पर विचार नहीं कर रहे हैं। धारा 11(2) यह प्रावधान करती है कि कर के माध्यम से एकत्र की गई कोई भी चीज़, हालांकि यह वास्तव में सूची II की प्रविष्टि '54 के तहत अधिनियमित कानून के तहत कर के रूप में देय नहीं

है, सरकार को भुगतान किया जाना चाहिए। हमारी राय में यह स्थिति ओरिएंट पेपर मिल्स लिमिटेड के मामले की स्थिति से बिल्कुल अलग है।

अशोक मार्केटिंग लिमिटेड बनाम बिहार राज्य और अन्य, (3) में, उनके आधिपत्य ने देखा: -

“संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 54, सूची II में कर लगाने, कर एकत्र करने के लिए मशीनरी निर्धारित करने, अधिकारियों को नामित करने, जिनके द्वारा दायित्व लगाया जा सकता है, को अधिकारी के अधिकार, दायित्व और क्षतिपूर्ति निर्धारित करने की शक्ति शामिल है। प्रवेश के तहत राज्य विधानमंडल 'वस्तुओं की बिक्री और खरीद पर कर' से संबंधित मामलों के संबंध में कानून बनाने के लिए सक्षम हो सकता है। लेकिन उपधारा (3), (4), और (5) में निहित प्रावधान एक डीलर को मजबूर करता है जिसने जानबूझकर या गलती से क्रेता से एक राशि इस अभ्यावेदन पर वसूल की है कि वह कर के भुगतान के लिए खुद को वसूलने के लिए इसे वसूल करने का हकदार है। , राज्य को उस राशि से अधिक का भुगतान करना प्रविष्टि के लिए आवश्यक रूप से आकस्मिक नहीं माना जा सकता है। वास्तव में यह प्रावधान कर के रूप में एक राशि लगाने के लिए है जिसे लगाने में राज्य अक्षम है। केवल राज्य के पास धन जमा करने की मांग के रूप में दावे को छुपाकर संविधान के प्रावधानों को विफल करने की एक युक्ति की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिसे डीलर ने एकत्र किया है, लेकिन जिसे वह एकत्र करने का हकदार नहीं था।

आर.एस. जोशी, आदि बनाम अजीत मिल्स लिमिटेड और अन्य, आदि (4) में, यह आयोजित किया गया था: -

“धारा 37(1) और 46, बॉम्बे बिक्री कर अधिनियम (1959 का 51) (जैसा कि गुजरात राज्य पर लागू है) जो अधिनियमित करता है कि बिक्री कर के माध्यम से डीलरों द्वारा एकत्र की गई राशि, हालांकि माफी योग्य नहीं है, दंडात्मक रूप से सार्वजनिक खजाने से जब्त कर ली जाएगी, सूची II की प्रविष्टि 64 के साथ पढ़ी गई प्रविष्टि 54 द्वारा प्रदत्त विधायी शक्ति से परे नहीं हैं, और इसलिए, अधिकारातीत नहीं हैं। न ही वे प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 और 19(1)(एफ) का उल्लंघन करते हैं। धारा 37(1) में ज़ब्ती खंड पर रंग योग्यता के दोष का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। 'जब्ती' शब्द का अर्थ निषेधात्मक निर्देश के उल्लंघन के लिए दंड के समान होना चाहिए।'

(12) उनके आधिपत्य ने आर अब्दुल क्वाडर के मामले (सुप्रा) और अशोक मार्केटिंग के मामले (सुप्रा) पर ध्यान दिया और निम्नलिखित टिप्पणियां कीं: -

“तो, हम अशोक (ए.आई.आर. 1971 एस.सी. 946) से काफी हद तक असहमत हैं जबकि हम आम तौर पर अब्दुल कादर (ए.आई.आर. 1964 एस.सी. 922) से सहमत हैं। हमें यह उल्लेख करना चाहिए कि क्या बिक्री कर के रूप में अवैध रूप से एकत्र की गई राशि को जब्त किया जा सकता है, यह सवाल अशोक के मामले में विचार के लिए नहीं उठा था।

(13) यह पहले ही माना जा चुका है कि याचिकाकर्ता माल की बिक्री या खरीद से जुड़े नहीं हैं। वे निश्चित रूप से डीलर नहीं हैं। विधानमंडल मुख्य प्रावधान के प्रासंगिक और सहायक मामलों के संबंध में कानून बनाने के लिए भी सक्षम है, बशर्ते कि वे अनुसूची के प्राथमिक प्रमुख द्वारा प्रदत्त शक्तियों से संबंधित हों।

(14) ऊपर उल्लिखित अधिकारियों का अनुपात यह सुझाव देता है कि प्रविष्टि -54 के तहत कानून बनाने की आकस्मिक और सहायक शक्ति, वीआईएल अनुसूची की सूची // को याचिकाकर्ताओं की तरह माल की बिक्री या खरीद को पूरी तरह से कवर करने के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है।

(15) एन. पुलैया बनाम आंध्र प्रदेश सरकार, (5) में, एक मिल मालिक जिसका व्यवसाय केवल भाड़े के लिए चावल की पिसाई करना था और जो धान और चावल का व्यापारी नहीं था, ने आंध्र प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम में पेश किए गए प्रावधानों को चुनौती दी। , 1957, आंध्र प्रदेश सामान्य बिक्री कर (संशोधन) अधिनियम, 1963 द्वारा, जहां तक वे एक मिल मालिक से संबंधित थे, जो थोक बिक्री डीलर या खुदरा डीलर नहीं था, इस आधार पर कि प्रावधान राज्य के अधिकारेतर थे विधान मंडल। आंध्र प्रदेश राज्य ने निम्नलिखित रुख अपनाया: -

मिलर्स और हलर्स के कुछ लेन-देन की पुष्टि और जांच करने पर यह देखा गया है कि हॉलर्स और मिलर्स इसे चावल में बदलने की आड़ में बड़ी मात्रा में धान खरीद रहे हैं। किराये पर। परिणाम यह हुआ कि कर की एक बहुत बड़ी मात्रा खो गई और एकत्र नहीं की गई। इस चोरी को रोकने की दृष्टि से मिल मालिकों से संबंधित अधिनियम में लागू प्रावधानों को 1963 के संशोधन अधिनियम 16 द्वारा शामिल किया गया है। इनका उद्देश्य और उद्देश्य, रजिस्ट्रों के रखरखाव और रिटर्न जमा करने और पंजीकरण के संबंध में आवश्यकताएं हैं। हलर या मिलर जो वास्तव में डीलर नहीं है, उस पर डीलर के रूप में कर नहीं लगाया जाएगा और हलर या मिलर जो वास्तव में डीलर है, पिछले अधिनियम में खामियों के कारण कर से नहीं बच पाएगा। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए और मिल मालिकों द्वारा कर चोरी को समाप्त नहीं तो कम करने के लिए, इन विवादित प्रावधानों को पेश किया गया है।

(16) यह माना गया कि मुख्य प्रावधान बिक्री-कर की चोरी को रोकने के लिए थे जो बिक्री कर लगाने की शक्ति के लिए एक आकस्मिक और सहायक शक्ति थी और इसलिए, वे राज्य विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं थे।

(17) एन. पुलय्या के मामले (सुप्रा) के अनुपात को याचिकाकर्ताओं के खिलाफ इस कारण से नहीं दबाया जा सकता है कि इसमें मिलर्स और हलर्स पर बिक्री-कर के

भुगतान के बिना खुद खरीदारी करने का संदेह था, जबकि वर्तमान मामले में ऐसा नहीं है।

(18) चेक पोस्ट ऑफिसर, कोयंबटूर, और अन्य बनाम के.पी. अब्दुल्ला और ब्रदर्स-, (6) में, सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास जनरल सेल्स टैक्स एक्ट, 1959 की धारा 42 की उप-धारा (3) के दायरे की जांच की, जिसमें लिखा था निम्नानुसार:-

“चेक पोस्ट या बैरियर के प्रभारी अधिकारी, या पूर्वोक्त रूप से सशक्त अधिकारी के पास किसी भी सामान को जब्त करने और जब्त करने की शक्ति होगी जो किसी भी वाहन या नाव द्वारा परिवहन के अधीन है और इसके अंतर्गत नहीं आता है;

(i) बिक्री का बिल या डिलीवरी नोट।

(ii) माल वाहन रिकॉर्ड, ट्रिप शीट या लॉग बुक, जैसा भी मामला हो, और

(iii) ऐसे अन्य दस्तावेज़ जो इसके तहत निर्धारित किये जा सकते हैं

धारा 43 और 44

बशर्ते कि जब्ती का आदेश देने से पहले अधिकारी प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देगा और निर्धारित तरीके से पूछताछ करेगा।

उनके आधिपत्य ने देखा:

“संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 54 राज्य विधानमंडल को माल की बिक्री या खरीद

पर करों के संबंध में कानून बनाने के लिए अधिकृत करती है। एक विधायी प्रविष्टि केवल शक्तियों का प्रतिपादन नहीं करती है: यह कानून के क्षेत्र को निर्दिष्ट करती है और इसके साथ व्यापक आयात और महत्व जुड़ा होना चाहिए। किसी निर्दिष्ट विषय पर कानून बनाने की शक्ति में उन मामलों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति शामिल है जिन्हें उचित और उचित रूप से समझा जा सकता है। इसलिए, एक कर प्रविष्टि, विधानमंडल को कर चोरी को रोकने के प्रावधानों सहित सहायक या आकस्मिक मामलों के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करती है। धारा 42 की उप-धारा (1) और (2) का उद्देश्य बिक्री-कर की चोरी को रोकने के लिए मशीनरी स्थापित करना है। लेकिन, हमारे निर्णय में, किसी वाहन में ले जाए गए माल को जब्त करने की शक्ति को माल की बिक्री या खरीद पर करों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति में निष्पक्ष और उचित रूप से शामिल नहीं कहा जा सकता है। उप-धारा (3) के अनुसार, चेक पोस्ट या बैरियर के प्रभारी अधिकारी को किसी भी वाहन में ले जाए जा रहे किसी भी सामान को जब्त करने और जब्त करने की शक्ति है, यदि वे तीन उप-में निर्दिष्ट दस्तावेजों द्वारा कवर नहीं किए गए हैं। खंड। उपधारा (3) मानती है कि चेक पोस्ट के पास वाहन में ले जाए गए सभी सामान वे सामान हैं जो मद्रास राज्य के भीतर बेचे गए हैं

और जिनके संबंध में बिक्री कर का भुगतान करने का दायित्व उत्पन्न हुआ है, और चेक पोस्ट अधिकारी को अधिकृत करता है, जब तक कि निर्दिष्ट न हो सामान को जब्त करने और जब्त करने के लिए और प्रभावित व्यक्ति को जब्ती के बदले जुर्माना देने का विकल्प देने के लिए बैरियर के चेक पोस्ट पर दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं। इस धारणा पर अधिनियमित प्रावधान कि एक राज्य से दूसरे राज्य में वाहन में ले जाए गए माल को राज्य के भीतर बिक्री के बाद परिवहन किया जाना अनुचित है। किसी भी स्थिति में उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त सभी वस्तुओं को जब्त करने और जब्त करने और जुर्माना लगाने की शक्ति

वाहन चाहे माल बेचा गया हो या नहीं, बिक्री कर लगाने की शक्ति के लिए आकस्मिक या सहायक नहीं है। एक व्यक्ति अपना सामान, यहां तक कि व्यक्तिगत सामान के रूप में, एक राज्य से दूसरे राज्य या उपभोग के लिए ले जा रहा है, क्योंकि वह धारा की उपधारा (3) के खंड (i), (ii) और (iii) में निर्दिष्ट दस्तावेजों का उत्पादन करने में असमर्थ है। 42, उसका माल जब्त होने का खतरा है। धारा 42 की उप-धारा (3) के तहत शक्ति को बिक्री-कर लगाने के लिए कानून बनाने की शक्ति के लिए सहायक या आकस्मिक नहीं कहा जा सकता है।

(19) के. पी. अब्दुल्ला के मामले (सुप्रा) का अनुपात इनलप इंडिया लिमिटेड बनाम पंजाब राज्य और अन्य में दबाया गया था, (7), जिसमें पंजाब जनरल सेल्स टैक्स अधिनियम की धारा 14-बी की उपधारा (8) की शक्तियाँ थीं जांच की गईं और इसे राज्य विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र से बाहर माना गया।

(20) तत्काल मामले में, अधिनियम की धारा 38 में प्रावधान है कि एक समाशोधन या अग्रेषण एजेंट या दलाई अपना व्यवसाय तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह मूल्यांकन प्राधिकारी से लाइसेंस प्राप्त नहीं कर लेता है और इसके अलावा उसके लिए मूल्यांकन प्राधिकारी को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। सामान के लेन-देन के संबंध में विवरण और जानकारी ऐसे प्रारूप और तरीके से दी जाएगी जो निर्धारित की जा सकती है। उल्लंघन की स्थिति में, वह उस सामान के मूल्य के 20 प्रतिशत के बराबर राशि का जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी है जिसके संबंध में कोई विशेष या जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। एक समाशोधन या अग्रेषण एजेंट या दलाई माल की बिक्री या खरीद के लेनदेन के लिए एक अजनबी है। वह बिक्री-कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है और न ही वह इसकी चोरी के लिए जिम्मेदार है क्योंकि वह डीलर नहीं है। इसके अलावा, लेन-देन में बिक्री-कर की चोरी का अनुमान लगाने का शायद ही कोई औचित्य है, जिसके संबंध में एक एजेंट या दलाई को अधिनियम की धारा 38 के तहत मूल्यांकन प्राधिकारी को

विवरण और जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। इसी तरह, लेन-देन में बिक्री-कर की चोरी मानना गलत होगा, जिसका विवरण और जानकारी एक एजेंट या दलाई मूल्यांकन प्राधिकारी को प्रस्तुत करने में विफल रहा है। इसके अलावा, बिक्री-कर की चोरी के संबंध में जिम्मेदारी, यदि कोई हो, डीलर की है और इसे उचित रूप से एजेंट पर नहीं थोपा जा सकता है; दलाई. विचाराधीन मामला काफी हद तक के.पी. अब्दुल्ला के मामले (सुप्रा) के अनुपात से कवर होता है। बिक्री-कर का भुगतान करने के लिए एजेंट या दलाल का कोई दायित्व नहीं है या उसके भुगतान से बचने के लिए उसके खिलाफ कोई प्रयास या संदेह नहीं है; यह नहीं माना जा सकता है कि अधिनियम की धारा 38 में निहित प्रावधान राज्य विधानमंडल की संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2, प्रविष्टि 54 के तहत बिक्री कर लगाने की शक्ति के लिए सहायक और आकस्मिक हैं।

(21) मूल चंद-चूनी लाई बनाम श्री मनमोहन सिंह, सहायक उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारी, चुंगी प्रभारी, शम्हू बैरियर, जिला पटियाला और अन्य में, (8) (पूर्ण पीठ) उपधारा (6), (7) के अधिकार और 1974 के संशोधन अधिनियम 9 द्वारा प्रस्तुत पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम की धारा 14-बी की (8) की जांच की गई। ये हुआ था: -

“यह तुरंत ध्यान दिया जाएगा कि धारा 14-बी (6), जैसा कि यह मूल रूप से था, दस्तावेजों के अंतर्गत नहीं आने

वाले किसी भी सामान की जब्ती के लिए प्रदान किया गया था और धारा 14-बी (8) के संबंध में सभी सामानों की जब्ती के लिए प्रदान किया गया था। जो घोषणा झूठी थी। जब्ती इस सवाल के बावजूद की जा सकती है कि क्या कर चोरी का कोई प्रयास किया गया था। जब्ती के दोनों प्रावधानों में अंतर्निहित यह बुनियादी लेकिन अनुचित धारणा, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के मामले में था, यह थी कि माल को बिक्री के बाद राज्य के भीतर ले जाया गया था। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मामले में हुआ था, यह निर्दिष्ट करने का कोई प्रयास नहीं किया गया कि कौन सा सामान जब्त किया जा सकता है। प्रावधानों को बाल राज तुली, जे. और डिवीजन बेंच ने के.पी. अब्दुल्ला के मामले में निर्धारित सिद्धांतों के अंतर्गत आने पर विचार किया। लेकिन अब स्थिति बिल्कुल अलग है। जुर्माना लगाने का नया प्रावधान [संशोधित धारा 14-बी(7)] अब किसी भी धारणा पर आधारित नहीं है कि बिक्री के बाद माल राज्य के भीतर ले जाया गया था। इसका वर्तमान आधार कर चोरी का प्रयास है और यह जुर्माना लगाने से पहले एक शर्त निर्धारित करता है। मिसाल की शर्त यह है कि अधिकृत अधिकारी को एक फंडिंग दर्ज करनी चाहिए कि अधिनियम के तहत कर से बचने का प्रयास किया गया है। संभवतः इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि बिक्री कर की चोरी की रोकथाम बिक्री कर लगाने के लिए एक आकस्मिक या सहायक शक्ति है और संविधान की अनुसूची VII की सूची II की प्रविष्टि 54 के अंतर्गत आती है। धारा

14-बी(7), यदि एईटी के तहत देय कर से बचने का प्रयास किया गया है, तो माल को हिरासत में लेने और जुर्माना लगाने का प्रावधान है, इसलिए इसे संवैधानिक मंजूरी के बिना नहीं माना जा सकता है। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि जो सामान हैं हिरासत में लिए जाने को भी धारा 14-बी(6) में व्यापार के लिए रखे गए सामान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है और उचित और वास्तविक दस्तावेजों द्वारा कवर नहीं किया गया है।

(22) एक समाशोधन या अग्रेषण एजेंट और दलाई अधिनियम की धारा 38 के तहत लाइसेंस के बिना अपना व्यवसाय नहीं कर सकते हैं और उनके लिए मूल्यांकन प्राधिकारी को संभाले गए माल के लेनदेन के संबंध में विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है और डिफॉल्ट रूप से जुर्माना भुगतना होगा। माल के मूल्य के 20 प्रतिशत के बराबर जिसके संबंध में विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अधिनियम की धारा 38 में निहित प्रावधानों के विवरण को ध्यान में रखते हुए यह मानना मुश्किल है कि यह मूल चंद, चूनी लाई के मामले (सुप्रा) के अनुपात में आता है और राज्य विधानमंडल के पास कर लगाने की सहायक या आकस्मिक शक्ति है। प्रविष्टि 54 के तहत बिक्री कर, सातवीं अनुसूची की सूची 2।

(21) उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, अधिनियम की धारा 38 राज्य विधानमंडल के अधिकारातीत है क्योंकि यह न

तो सीधे तौर पर सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 54, सूची II में शामिल है और न ही यह उसके आनुषंगिक है। अधिनियम की धारा 38 के परिणामी होने के कारण नियम 53 को भी बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

(22) परिणामस्वरूप, वीएमटी याचिका की अनुमति दी जाती है और अधिनियम की धारा 38 और नियमों के नियम 53 को असंवैधानिक करार दिया जाता है और उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ताओं को उसमें निर्धारित रिटर्न दाखिल करने के लिए बाध्य करने से रोका जाता है। मूल्य के हिसाब से कोई आर्डर नहीं।

प्रेम चंद जैन, ए.सी.जे.-में सहमत हूं।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिये निर्णय का अंग्रेज़ी सस्करण प्रामाणिक होगा

और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

सचिन कुमार सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

नूँह, हरियाणा